आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 26.11.2024
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार चार सौ करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी।
- राज्य में संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज दिए जाने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट तलब की।
- चमोली जिले के गैरसैंण ब्लाक में सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू।
- यू०पी०सी०एल प्रदेशभर के दूरस्थ स्टेशनों की निगरानी के लिए वास्तविक समय डेटा अधिकरण प्रणाली की स्थापना कर रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमण्डल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार 481 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में कल रात मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्वनि वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनजीर्वित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15 हजार क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। यह सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल तथा पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए अनुसंधानपरक लेखों और जरनल प्रकाशन को देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता के लिए छह हजार करोड रूपये आंवटित किए गए हैं।

ई०एस०आई कवरेज

राज्य में संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा– ई०एस०आई कवरेज दिए जाने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने शहरी विकास सचिव से नगर निगमों और नगर निकायों में दैनिक और संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज देने के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी नगर पालिकाओं और निकायों की तत्काल समीक्षा कर उनमें कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मचारियों तथा श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनिवार्य रूप से आच्छादित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबन्धन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओं में कार्यरत संविदा और सामान्य श्रमिकों को भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

संविधान दिवस

देश आज संविधान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 1949 में पहली बार भारतीय संविधान को अपनाया गया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। यह प्रत्येक भारतीय के गौरव, अधिकार और सम्मान का रक्षक भी है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबासाहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए कहा कि विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है।

आदर्श गांव सारकोट

चमोली जिले के गैरसैंण ब्लाक में सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिले के सभी विभागों की बैठक लेते हुए सारकोट गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सारकोट में वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा। उन्होंने आदर्श ग्राम सारकोट में सभी बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं के साथ सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में आंगनबाडी भवन, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और रंगरोगन के साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

आरटी–डी०ए०एस स्थपाना

यू०पी०सी०एल की ओर से प्रदेशभर के 215 नग उप संस्थानों पर वास्तविक समय डेटा अधिकरण प्रणाली–आरटी–डी०ए०एस की स्थापना की जा रही है। इसकी सहायता से ऑनलाईन डाटा संकलित करने और विश्लेषण करने के साथ दूरस्थ स्टेशनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। इसकी सहायता से ऑनलाईन डाटा संकलित करने और विश्लेषण करने के साथ दूरस्थ स्टेशनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। इससे बिजली की नियोजित और अनियोजित कटौती का पता लगाया जा सकेगा और विद्युत वितरण नेटवर्क की विश्वसनीयता को सटीक रूप से मापने में मदद मिलेगी।

यह प्रणाली प्रदेश भर के उन उपसंस्थानों में शुरू की जाएगी, जिनके अन्तर्गत 25 हजार से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं। वर्तमान तक योजना के तहत प्रदेश में कुल 103 उपसंस्थानों पर इस प्रणाली की स्थापना की जा चुकी है। शेष उपसंस्थानों पर आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से आरटी–डी०ए०एस प्रणाली की स्थापना का कार्य पूरा किया जाएगा।

पीएम–आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), हर परिवार को आवास देने का सपना साकार कर रही है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 34 हजार से अधिक आवास बन चुके हैं। राज्य सरकार ने योजना के दूसरे चरण के लिए भी केंद्र सरकार के साथ अनुबंध कर लिया है, जिसमें लाभार्थियों को अधिक आर्थिक अनुदान प्राप्त हो सकेगा। भारत सरकार ने इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की घोषणा की है। इसमें केंद्र ने अब प्रति आवास केंद्रांश डेढ़ लाख रुपए से बढाकर दो लाख पच्चीस हजार रुपए कर दिया है।

गौरतलब है कि पीएम–आवस योजना के तहत राज्य में पहले चरण में 64 हजार तीन सौ इक्कानब्बे आवास स्वीकृत किये गये हैं।

निरीक्षण

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गोपेश्वर में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हल्द्वापानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से उपचार कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना को पूरा करने के लिए सितंबर माह का समय निर्धारित था, लेकिन मानसून के चलते दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रो पाइलिंग का काम चार चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वॉल का काम किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूस्खलन से प्रभावित भवनों में लगे क्रैकोमीटर की भी जांच की, जिसमें दरारें बढ़नी की घटना नही पायी गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यो को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हल्द्वापानी में निर्माण कार्यो की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे पर तत्काल डामरीकरण कराने को भी कहा, ताकि यहां पर वाहनों की सुगमता से आवाजाही बनी रहे।

एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर –

केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। दैनिक जागरण लिखता है– राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हरी झंडी, बिना उर्वरक कृषि करेंगे किसान, केंद्र सरकार ने दी दो हजार चार सौ इक्कासी करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी। वहीं, हिन्दुस्तान समाचार पत्र कैबिनेट के एक अन्य फैसले पर लिखता है– पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी होंगे।

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत की ख़बर को भी अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है– अदाणी मुद्दे पर हंगामें की भेंट चढ़ा सत्र का पहला दिन। वहीं, अमर उजाला प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है– जनता ने जिन्हें नकारा, वे संसद को कंट्रोल करने की कर रहे कोशिश।

14 और नई नीतियां हुईं तैयार कैबिनेट से जल्द लगेगी मुहर, इस ख़बर के शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है– सशक्त उत्तराखंड /25 : कृषि–उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, वितत विभाग से जुड़ी हैं नीतियां।

वरिष्ठ आई.पी.एस अधिकारी दीपम सेठ के उत्तराखंड पुलिस में महानिदेशक के पदभार संभालने की ख़बर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है– आमजन को भरोसा व अपराधी को बना रहे डर, पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ने गिनाई पुलिस की प्राथमिकतांए।

उत्तराखंड में श्रमिकों को ईएसआई का लाभ नही ंदेने के मामले में कार्रवाई पर हिंदुस्तान समाचार पत्र की ख़बर है– श्रम विभाग ने पन्द्रह हजार इकाईयों को भेजा नोटिस। मुख्य सचिव ने धीमी प्रक्रिया पर जताई नाराज़गी।